



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



4 सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं : जूली

6 कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

7 फिल्मों ने सिखाया अनजान चीजों से डरना नहीं : कियारा आडवाणी

फर्स्ट टेक

चीन की कम्पनी 'एवरग्रांडे' के संस्थापक को उम्रकैद की सजा

हांगकांग/एपी। चीन की संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी 'एवरग्रांडे' के संस्थापक हुई का यान को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी कंपनियों पर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिणी चीन के शेनजेन शहर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। वर्ष 2020 में जब चीनी अधिकारियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक कर्ज लेने पर रोक लगाई, तब एवरग्रांडे कंपनी पर 300 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की देनदारियां थीं और वह कंगाल हो गई थी। इस फैसले को एवरग्रांडे मामले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शेनजेन शहर की एक अदालत ने 67 वर्षीय हुई (जिन्हें यू जियायिन भी कहा जाता है) और उनकी कंपनी 'एवरग्रांडे' को बहुत बड़े आर्थिक घोटाले का दोषी पाया है।

अमेरिकी राजदूत पहली लड़ाख यात्रा पर पहुंचे

लेह/भाषा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने लड़ाख की अपनी पहली यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार को संगम में जंरकार और सिंधु नदियों के संगम स्थल पर रिवर राफ्टिंग की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोर के लड़ाख दौरे का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के अग्नू प्राकृतिक परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करना था। अमेरिकी राजदूत बुधवार को श्रीनगर पहुंचे थे जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की।

'समाधान समारोह' यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि दोनों पक्षों को लगे कि उनकी जीत हुई : सूर्यकांत

नई दिल्ली/भाषा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की 'समाधान समारोह' पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का मध्यस्थता के जरिए इस तरह समाधान करना है कि दोनों पक्षों को यह महसूस हो कि उनकी जीत हुई है। उच्चतम न्यायालय के 'समाधान समारोह' के तहत मामलों के लंबित रहने की समस्या से निपटने के लिए मध्यस्थता और विवादों के सहमति से समाधान के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पहल के जरिए पक्षकारों को आपसी सहमति से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद की जाती है।

21-07-2026 22-08-2026
सूर्योदय 6:27 बजे सूर्यास्त 5:59 बजे

BSE 77,537.72 (+628.04)
NSE 24,231.85 (+153.55)

सोना 16,404 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 260,000 रु. प्रति किलो

मिशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com



केलाहा मण्डेला, मो. 9828233434

जाहिल लोगों

ये लौन लिला उड़या देंगे, हैं कौन कुछ प्यार तो। संसद तक पर हमला करते, हैं क्या मकसद यह खोलो तो। आखिर किसका यह देश कहां, कथनी करनी को तोलो तो। जाहिल लोगों कुछ पल को ही, अपनी औकात टटोलो तो।

भारत-जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किया समझौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य सहयोग में तालमेल बढ़ाने का संकल्प लिया। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई तथा बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के प्रयासों का कड़ा



विरोध किया।

दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि राजनाथ और कोइजुमी ने मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया, दोनों मंत्रियों ने बढते वैश्विक तनाव के दौर में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल के आकलन को साझा करने के महत्व पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि वे नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई तथा बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। यह टिप्पणी चीन की ओर संकेत के

रूप में देखी जा रही है, क्योंकि भारत और जापान दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं।

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन' (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रुपरेखा उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के तहत जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र की जागरूकता से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान और खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। राजनाथ और कोइजुमी ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को ठोस रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाने पर सहमति जताई।

बचाव



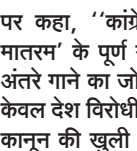
उत्तराखंड के धारचूला में तावाघाट के पास कुलागाड पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद भारतीय सेना के कुमाऊं स्काउट्स के जवानों ने बचाव अभियान चलाया और फंसे हुए 300 से अधिक स्थानीय लोगों को पर्यटकों की मदद की।

'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतरे गाने का कांग्रेस का फैसला 'राष्ट्रविरोधी' : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतरे गाने का पार्टी का फैसला 'राष्ट्र-विरोधी' है तथा इसका मकसद कानून की खुली अवहेलना कर 'वोट बैंक' के लिए तुष्टीकरण करना है। शाह ने राष्ट्रगीत को पूरा गाने के बजाय केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के फैसले का उल्लेख करते हुए देश के विभाजन के इतिहास का जिक्र किया और कहा कि 'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने के कारण देश को इसके परिणाम भुगतने पड़े। शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'

देशवासियों से यह अपील है कि कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे।



पर कहा, "कांग्रेस कार्यसमिति ने 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला किया है, वह न केवल देश विरोधी है बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।" शाह

पर (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी (के नेतृत्व वाली) सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसके परिणाम भुगत चुका है। उन्होंने कहा, "देशवासियों से यह अपील है कि कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें।" कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे।

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए

ढाका/भाषा।

सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बृहस्पतिवार को देश के नये राष्ट्रपति चुने गए। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये। मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष एवं जमात-



ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया। उन्होंने कहा कि आलमगीर को 255 मत मिले, जबकि ओली अहमद को 88 मत प्राप्त हुए।

डीके शिवकुमार ने अमित शाह से अपर भद्रा परियोजना की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया

चेन्नई/बंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपर भद्रा परियोजना के लिए केंद्र द्वारा घोषित 5,300 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राशि जारी होने में देरी से परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है। शिवकुमार ने यहां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्नाटक की पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी लेकिन अब तक यह राशि जारी नहीं की गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, उन्होंने शाह से कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

(बसवराज) बोम्मई सरकार के दौरान केंद्रीय बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। संसद में घोषणा किए जाने के बावजूद अब तक यह राशि आवंटित नहीं की गई

अमित शाह की उपस्थिति में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा का वचन दिया है मैंने : शिवकुमार

चेन्नई/बंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वचन दिया कि प्रस्तावित मेकेदातु बांध मामले में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा की जाएगी। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक अलग बैठक का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए पांच अरब घन फुट पानी (टीएमसी) इस्तेमाल करने के अलावा, प्रस्तावित मेकेदातु बांध में जमा बाकी पानी तमिलनाडु के लिए होगा। उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी को संबोधित करते हुए कहा, "बांध हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके लिए ही बनाया जायेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "ये एक राज्य में कारोबार करते हैं और निवेश कहीं और करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। ऐसे में राज्य सरकार को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे राशि कहां और किस तरह खर्च करें।" मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, शाह ने शिवकुमार के सुझाव से आंशिक रूप से सहमति जताई और उन्हें प्रकासी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करने को कहा।

महात्मा गांधी की पांडुलिपि रिकॉर्ड 16.2 करोड़ रु में बिकी

नई दिल्ली/भाषा। महात्मा गांधी के अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी को लिखे गए 688 ऑटोग्राफ वाले विचारों (जिनमें सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे विषय शामिल थे) के संग्रह को सैफ्रनआर्ट की नीलामी में 16.20 करोड़ रुपये में बेचा गया। यह नीलामी में बिके किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए एक विश्व रिकॉर्ड है। हिंगोरानी की पत्नी विद्या के निधन के बाद दो साल तक मार्गदर्शन, चिंतन और हौसला बढ़ाने वाले रोजाना हाथ से लिखे संदेशों को बाद में अर्थ फॉर द डे नाम की किताब में संकलित किया गया। ये संदेश दोनों के बीच हुए पत्राचार के सबसे निजी और सुरक्षित बचे हुए दस्तावेजों में से एक हैं।

'गांधी : फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी. हिंगोरानी' नाम की नीलामी में गांधी से जुड़ी चिट्ठियों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और निजी चीजों के 86 खंड शामिल थे। नीलाम करने वाली संस्था के अनुसार, इन पांडुलिपि में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (सांसारिक वस्तुओं या धन के प्रति मोह न रखना), निर्भयता, धार्मिक समानता, अस्पृश्यता निवारण,

प्रार्थना, रामनाम, सेवा, श्रम, भूख, कर्तव्य, स्वराज, नैतिक जिम्मेदारी, मौन, अंतराला की आवाज, अनासक्ति, आत्म-साक्षात्कार और ईश्वर की खोज जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। यह संग्रह न सिर्फ अहम राजनीतिक घटनाओं को दर्ज करता है, बल्कि गांधीजी के जीवन के बेहद निजी पहलुओं को भी सामने लाता है। इसमें भारत की आजादी की लड़ाई के जन्म-नेता और उस निजी व्यक्ति-जो अपने सबसे करीबी लोगों को सलाह, सांत्वना, अनुशासन और स्नेह देते थे-दोनों की झलक मिलती है। सैफ्रनआर्ट के सहसंस्थापक दिनेश वाजीरानी ने एक बयान में कहा, 'खंड 80' यानी गांधीजी द्वारा हिंगोरानी के लिए लिखे गए विचारों की एक शृंखला को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इसके दुर्लभ और ऐतिहासिक महत्व को और पुष्टा करती है। ये विचार एक साथ मिलकर इस बात की अनूठी मिसाल पेश करते हैं कि गांधीजी ने उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जिनका वे सार्वजनिक रूप से समर्थन करते थे; यही बात इसे उनके विचारों और कार्यों का एक बेहद बेशकीमती रिकॉर्ड बनाती है।

शीर्ष अदालत ने इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश पर सरकार की पुनर्विचार याचिका लौटाई

इस्लामाबाद/लाहौर/भाषा। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजने के अपने आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली सरकार की पुनर्विचार याचिका बृहस्पतिवार को लौटा दी।



शीर्ष अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 73 वर्षीय संस्थापक को अगले दो दिन के भीतर इस्लामाबाद के 'शिफा इंटरनेशनल अस्पताल' ले जाया जाए और 16 सितंबर के लिए निर्धारित अगली सुनवाई तक उन्हें वहीं रखा जाए।

सरकार ने पहले कहा था कि वह अदालत के आदेश को लागू करेगी, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आदेश पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने का अनुरोध किया। खबरों के अनुसार, अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने कागजात का पूरा संकलन नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार की याचिका लौटा दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार खामियों को दूर करने और जरूरी बदलाव करने के बाद नई याचिका दायर कर सकती है। हालांकि, 'पीटीआई' के महासचिव

सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपत्तियां उठाए जाने के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ले ली। उन्होंने कहा, 18 अगस्त के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करने का कोई बहाना नहीं है। इमरान खान साहब को तत्काल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। आज ही यह दिन है। न्यायमूर्ति शाहिद बहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अंतिम निर्देश जारी किए थे और सरकार को अस्पताल भेजने की समयसीमा बृहस्पतिवार आधी रात को समाप्त हो जाएगी।

खान की पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बृहस्पतिवार रात 11 बजकर 59 निमट तक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो यह शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करेगी।

खडोरा/थाना गुजरात के वडोदरा जिले में एक खड़ी बस के ऑटोमैटिक दरवाजे फंसे से सलामत वहीं बचे की मोत हो गई। पुलिस ने उपायसुचित कारो यह जानकारी दी। पुलिस उपायसुत अभिषेक शुभा के अनुसार, यह दुर्घटना घटना बुधवार शाम शहर के बाहरी इलाके में कम्पुराई थाना क्षेत्र स्थित एक गैराज में हुई। अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नया दिव्येश राविका के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गैराज के पास खेल रहा दिव्येश संभवतः खड़ी बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया और उसकी गर्दन उसमें फंस गई। उन्होंने बताया कि इसीसीटीवी फुटेज में दिखा कि गैराज में मौजूद दो लोगोंने न बचे को बचावे के लिए सब कुछ धका धक कर खोलो, लेकिन तब तक यह बेहोश हो नीचे गिर पडा। पुलिस उपायसुत (डीसीपी) गुणा ने बताया कि बसे को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



चंडीगढ़/भाषा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में शामिल नहीं होने की इजाजत दी थी क्योंकि उन्हें यहां पंजाब विश्वविद्यालय में एक परीक्षा में शामिल होना था।

पाटी का जंगिय लैन वाला शोष सस्था
सीडब्ल्यूसी की बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई
ली। प्रभयत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन
और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हुई
इस लंदी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खरगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल
गांधी, अन्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों
के अलावा कांग्रेस-शासित राज्यों के सभी
चार मुख्यमंत्री शामिल हुए।



नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में उच्चकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। सफदरजंग अस्पताल के सूत्रों ने यह

काजानकारी दी। अस्पताल ने अभी उनकी मृत्यु का निदान करार स्पष्ट नहीं किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस एनएल गौड़ा ने कहा कि १९८४ में सिंह विरोधी दंगों के समय कोचिंग के दौरान पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारा में भी आग लगा जाने से जुड़े मामले में १७ दिनों के सुनवाई के बाद सऊदी आई। कुमारारामाजी को उसके दोषी होने के लिए निर्णय दिया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि पांच सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में फरवरी २०२५ में उन्हें अपराध सामने था। तीन बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। कुमारारामाजी ने बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और वह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उन्होंने २०१८ में दोषी होने के लिए निर्णय दिया था।

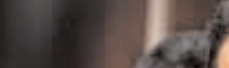
नई दिल्ली/भाषा। प्रकाश तरुण तेजपाल ने 2013 के खिलाफ बहुप्रतिपाद को मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ बहुप्रतिपाद को मामले में दोषसिद्धि का रुख किया। बंबई उच्च न्यायालय के छह आग्रस्त के आदेश के खिलाफ अधिकांश आदित्य सामन्तवार के जरिये अपील दायर की गई। इससे पहले, गोवा सरकार ने तहलका के पूर्व सपादक को सुनाई कि सजा बढ़ाने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। सरकार का कहना था कि इस मामले में उपरकैद की सजा दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ आदित्य सामन्त द्वारा पांच साल पहले न्यायालय को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें (तेजपाल को) दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

नये दिल्ली/पाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहजीवन साथी (लिव इन रिलेशनशिप) के रूप में वयस्कों के बीच संबंध शादी जैसा ही है और न तो माता-पिता, न ही दोस्त उनकी पसंद में दखल दे सकते हैं। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सहजीवन साथी के रूप में रह रहे एक युवक को लड़की के परिवार की ओर से मिल रही धमकियों के बाद उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कहा कि वयस्क होने के नाते उन्हें अपनी पसंद के साथी के चयन और उसके साथ रहने का 'पूरा अधिकार' है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नापुत्र/भावा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वसुधैवकुटुम्बक राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतर गाने के फेरते को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की तथा इसे संविधान के खिलाफ और विपक्षी दल की 'मानसिक गुलामी' का परिचायक बताया।

कांग्रेस के दौरान पत्रकारों से यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 22 अमृत को पुणे में होने वाला सहूल गांधी का छात्रों की गुंजायमान सिर्फ कांग्रेस नेताओं द्वारा



चलाए जा रहे कॉलेजों के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम खुली बातचीत के बजाय एकतरफा भाषण (मोनोलॉग) जैसा होगा। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक	इकाई (सीडब्ल्यू 1937 फ्रैंसला के सभी सिर्फ दो
--	--

इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडीब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फ़ौसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के सिर्फ़ दो ही अंतरित गाये जायेंगे। कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को वंदे मातरम् को लेकर गुजरात में भरी अमित शाह द्वारा निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छात्रों तथा राम मंदिर से कथित चंदा चोरी जैसे विषयों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्र गीत को लेकर विवाद खड़े करना चाहती है, जबकि उसके (भाजपा) के लोग झूठे और 'नकली' राष्ट्रवादी हैं।

पाटी महासचिव जयराम रमेश ने यह संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 'ट्राइड' (परखे जा चुके) और 'टायर्ड' (थक चुके) हैं तथा अब उन्हें 'जल्द ही

रिटायर' हो जाना चाहिए।
रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह राम शीश शाह और भाजपा छात्रों के मुद्दे और राम मंदिर से चंदा चोरी तथा आस्था के साथ 'धोखा' जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके महा में फंस्ने वाली नहीं है। कांग्रेस जलसचिव ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा 1937 में कई मातस्म के संदर्भ में पारित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए

A group of people are walking outdoors at night. In the center, a woman in a purple floral dress is walking. To her left, a man in a white shirt and glasses is walking. To her right, a man in a white shirt and a striped scarf is walking. They are all walking towards the camera. The background is dark, and there are some lights visible.

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली / थापा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षा की राजनीतिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाली पुनर्गठित मीठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े चार सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर बुधवार को को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किताबों का संघीकरण किया जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रेग्मेश ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के समर्थन में शुद्धिकरण का हवाला देते हुए यह भी कहा कि व्यक्तियों का शुद्धिकरण पाप है, किताबों का संघीकरण शाप है।

उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि 'नागपुर कोर्टी फॉर एजुकेशनल रिसाइटिंग एंड ट्रबल-मेकिंग' (एनसीआरटी) की टोली द्वारा किताबों का पुनर्लेखन और संस्थाओं का 'संघीकरण' करने का रहा है। एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाली टीम का पुनर्गठन किया है। इसे

सांस्कृतिक जड़ों, भारतीय ज्ञान परंपरा और समाजोपदेशिता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का दायित्व सौंपा गया है। टीएम में कम से कम चार सदस्य ऐसे हैं, जिनके आरएसएस से प्रथम या अवलम्ब संबंध बताए जा रहे हैं। टीएम को कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक नवंबर तक और कक्षा 12वीं की पुस्तक अप्रैल वषर् जुलाई तक तैयार करने को कहा गया है। इस मुद्दे पर पूरे गण सचल के जवाब में रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कोटा में 17 जून को 'छात्रों की गुंठ' कार्यक्रम के दौरान भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तीन सुझावों 'निजीकरण, केंद्रीकरण और 'संघीकरण' का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा था कि शिक्षा व्यवस्था तीन 'सी' 'केंद्रीकरण, शिक्षाव्यवस्था और सांसादयिकीकरण' से प्रभावित है। रमेश ने कहा, 'एससीआईटी ने जो किया है, वह पिछले 12 वर्षों से हो रहा है, चाहे शिक्षा मंत्री के रूप में स्मृति इंदिरा जी या प्रांशज जायवकर, रमेश पोखरियाल निशंक', धर्मंद प्रधान व प्रह्लाद जोशी'। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सचलका सूत्रा आरएसएस है। रमेश ने कहा, 'एक तरफ वे व्यक्तियों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, जो पाप हैं और दूसरी तरफ पाठ्यपुस्तकों का 'संघीकरण' कर रहे हैं, जो शाप हैं'।

त्रेशूर/भाषा। अभिनेता
यकाश राज ने
बृहस्पतिवार को कहा
के नीट प्रश्नपत्र लीक के
खिलाफ युवाओं के
वैरोध-प्रदर्शन के बाद
देश में 'फासीवादी

[illegible]

उन्होंने कहा कि युवाओं ने सरकार से सलाह कदा है कि वे उठे हुए नहीं हैं और उनकी राजनीति को समझते हैं। उन्होंने कहा, "पहली बार देश के नागरिकों और युवाओं ने कहा है, हम आपसे नहीं डरते।" उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की जलरुचि भी, जो बात कह सके। राज ने कहा कि किसानों, जज्दों और सरकारी कर्मचारियों के कई लोगों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किए हैं लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी और जमीन खोने का डर था। उन्होंने कहा, लेकिन इन युवाओं के पास उठने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए राज ने कहा कि करीब एक लाख लोग आए हैं, जबकि चार लाख अन्य लोग राष्ट्रीय विरोधधानी की सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि युवाओं ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि सवाल प्रश्न पूछा।

(जीएसी) को निर्देश दिया कि वह
 न्यायालय को बुधभाति को केन्द्र
 (जीएसी) की शाखात अपील समिति
 (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह
 (जीएसी) साई बाबा को निशाना नह
 आले कथित रूप से भडकाऊ और
 अपीलसमितिजक पृथ्वी वीडियो को
 (जीएसी) के मांग वाला शाखात पर
 विचार करो। न्यायमूर्ति चरण कांत
 न्यायचम प्रोद्गोषी की मंत्रालय,
 (जीएसी) अपील समिति
 (जीएसी) और गुला को नोटिस
 जारी कर इस संबंध में नया आवेदन
 दाखिल करने वाले 'श्री साईबाबा
 संरंथाना न्याय, शिरडी' की याचिका
 पर जयमा गां है।

इससे पहले उस न्यायालय ने आपसिजनिक को सात दिनों के भीतर आपसिजनिक को खिडियो हटाने के मुद्दे पर निर्ण लेने का सुनिश्च दिया था। पर आपसिजनिक को खिडियो हटाने के बाद सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जीएसपी ने 13 अगस्त को ही एक आदेश पत्रित कर ऐसे खिडियो और लेखों को को हटाने का निदेश दे दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ता न्याया प्रतनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिकाता मोमोद और और अधिकाता प्राची दुवे ने दलील दी कि आपसिजनिक सगसायी को पूरी तरह से नहीं हटया गया है और कुछ खिडियो तथा लेख अजर भी हटाने पर मौजुद हैं।

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मा सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर बृहस्पतिवार कहा कि पापा ऊपर से अपनी खूबसूरत सोनिया

गांधी जी आत्मकथा इस साल नवंबर में बाजार में आने वाली है। राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'उन्हें गर्व है कि उनकी मां की कहानी उन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, जो उनसे प्यार करते हैं। उनका कहना है कि वह जानते हैं कि सोनिया जैसी ब्रह्मदेहि नजि जीवन जीने वाली महिला के लिए दुनिया के सामने अपनी खुबसूरत कहानी रखना कितना कठिन रहा होगा।

सांनिया गांधी नवंबर में अपनी आत्मकथा लेकर आएंगी, जिसमें यह भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में से एक में पैदा होने के बाद अपने जीवन, पति राजीव गांधी की हत्या के उस दुःखद दौर और 2004 में प्रधानमंत्री पद अस्वीकार करने सहित कई निजी अनुभव साझा करेंगी। अमेरिकी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/चेन्नई/भावा।
 करलम के मुख्यमंत्री जी. डी.
 सतीशन ने बहुपक्षीय को चेन्नई में
 दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की ३१वीं
 बैठक में मल्लुपारियार बांध का मुद्दा
 उठाया और स्वास्थ सेवा,
 बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण
 एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में
 सहकारी संस्थाओं की आवश्यकता
 पर जोर दिया। सतीशन द्वारा
 मोक्ष मीटिंग एवं 'एक्स' पर
 नुमासा, मुख्यमंत्री ने 'पेट' में
 सतीशन से जुड़े जिन मुल्लु मुद्दों को
 उठाया, उनमें मल्लुपारियार बांध
 का मुद्दा भी शामिल है।
 सतीशन ने कहा कि केरलनाडु
 के सतीशन से जुड़े जिन मुल्लु मुद्दों को
 उठाया, उनमें मल्लुपारियार बांध
 का मुद्दा भी शामिल है।

पर राहुल ने क
सोनिया को गर्व



काकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस की 'एक्रेडेड' 'ऑफ नॉन' ने गैंगलवार को घोषणा की कि सोनिया गांधी की आत्मकथा 'सोनीया-ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। हालांकि, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भारत में पुरस्कृत के मेमोचन की तारीख की ओरी पुष्टि नहीं की है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'मैंने अपने आपको आपा को आखिरी बार 35 साल से अधिक समय पहले साक्षात्कार था। जिस दिन पापा हमें छोड़कर गए, उस दिन से मैंने आपाको जीवन की हर चुनौती का साथकाम असीस साहस और गिरिमा के साथ करके देखा है।'

उन्होंने कहा, “केवल प्रियंका और मैं ही वास्तव में जानते हैं कि

लाल तैयार है। उन्होंने कहा कि नवलोकन के डिजाइन, स्थान और प्रभाव-निर्माण का ज़िम्मा तमिलनाडु में संभालेगा जबकि इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार पर दहन करेगा। तमिलनाडु भाषावादाचार कहता है कि पुराना नाला खोज सुरक्षित है, जबकि केंद्र सरकार को यह कहना है कि केंद्र सरकार असुरक्षित है और जलस्तर अधिकतर स्थिति में यदि बांध टूटता है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के जान को खतरा हो सकता है। कलम में पुराना बांध का उपयोग नहीं है। बंद किए जाने की मांग की है। बंद किए जाने में अपनी सरकार की सतीशनाथ ने अपनी सरकार की विनियमन (विकास और विनियमन) अधिनियम में हाल में किए गए संशोधनों को वापस लेने की जरूरत के लिए संसद की सदस्य संस्था बहाल किया गया है। संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की आवश्यकता का मामला भी उठाया

मे देख रहे होंगे

आपने किन परिस्थितियों का सामना किया और पापा के जाने के बाद आपका जीवन कितना कठिन था?" राहुल गांधी ने कहा, "मुझे खुशी है और यह भी कि आपकी कहानी-बिलॉगिंग: ए जर्नी ऑफ लव- आखिरकार उन लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जा रही, जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप जैसी निजी जीवन को महत्व देने वाली शक्तियुक्त के लिए दुनिया के सामने अपनी खुबसूरत कहानी रखना कितना कठिन था।"

उन्होंने कहा कि “आज, अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर, यह कल्पना कर सकते हैं कि पायाऊपर से मुकुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे।” अल्फ्रेड ए. नॉफ़ की वेबसाइट के अनुसार, अक्सरथा की शुरुआत इंग्लैंड के कैम्ब्रिज से होती है, जहां 1965 में 19 वर्षीया छात्रा सोनिया मायनो को पहली नजर में उस खूबसूरत युवक से मोहबहत हो जाती हैं” जिससे आगे चलकर उनका विवाह होता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भावा। कथित ठग
चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को जेल
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम
नी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद
रोवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को
पत्र लिखकर "तीन और बड़े

का खुलासा करने की है। पत्र में कहा गया है, रीयाल जी, सत्येंद्र जी और सी, आपके भ्रष्टाचारों को करने के लिए एक और कदम। मैं आगे बढ़ रहे हूँ। 2 में किए गए खुलासे सही हैं। अब 'शराब नीति' बाद अगला नंबर 'जल' है। अभी तीन और मामले

A man with a beard, wearing a yellow and black patterned shirt, is being escorted by police officers. One officer in a khaki uniform is visible on the right, and another is partially visible on the left. The man is looking towards the camera.

बाकी हैं, और अब ये उजागर होंगे।' इसमें कहा गया है, आपके 'तीन ओर घोटालों' और 'भ्रष्टाचार' का तीन ओर महत्वपूर्ण विभागों में जल्द ही खुलासा किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। जल्द ही 'आप'- 'एनीटाइम, ऑलवेज पार्टी ऑफ स्कैम'-की पहचान घोटालों की पार्टी के रूप में और मजबूत होगी।'

लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने का
भूल जाइए; जनता आप सभी को
सबक सिखाने वाली है। जैसा दिहा
हुआ, वैसा ही पंजाब भी होगा।
की जनता आपके अहंकार और
घोटालेबाज पार्टी को इससे भी र
तरीके से नकार देगी। इसमें कहा
कि केजरीवाल के प्रॉक्सी द्वारा
युवाओं या 'जेन जी' को भड़क
याल काम नहीं करेगी और सुरेक्ष

पत्र में कहा गया है, "मैं आपको एक संकेत देकर कुछ स्पष्ट कर दूँ-आप और आपके प्राक्सी संस्थापक।" उम्मीद है, आपको 2015 और 2016 में मेरे साथ अपने जुड़ाव की याद होगी। हो सकता है कि आप लोगों को डेलुलुलु (भ्रम) हो, लेकिन मुझे सब याद है। मैं जल्द ही आपको चौकाऊंगा।"

कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना, कार्यवाही में शामिल नहीं हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुआ जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायकों ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध के मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी पर निराशा जताई और उनसे कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विधायी कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने के लिए कांग्रेस विधायकों की आलोचना की।

कुछ विधायी काम निपटाने व शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस विधायक बृहस्पतिवार की सुबह पोद्दार मूक-बधिर स्कूल पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश व मीडिया कवरेज पर कथित प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता और मीडिया को सरकारी स्कूलों की खराब हालत को उजागर करने से रोकने की कोशिश कर रही है। जूली ने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे के भी मांग की। बाद में ये विधायक जूली की अगुवाई में पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जब विधायकों ने समूह में विधानसभा में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ये विधायक विधानसभा



के बाहर धरने पर बैठ गए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के परिसर में प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना 'बाहरी लोगों' के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही लिखित मंजूरी के बिना स्कूल की गतिविधियों की कोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसकी टीम राज्य के उन स्कूलों का दौरा करेगी जिनकी हालत 'ठीक नहीं है'। इसके बाद ही राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रोक संबंधी यह आदेश निकाला। हालांकि, शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि इस

आदेश से आंगंतुकों पर पूरी तरह कोई रोक नहीं है। आज के धरना स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधायकों को नियमित दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तथा दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर तानाशाही वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और स्कूलों की हालत दिखाने पर लगाई गई रोक पर सवाल उठाए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के गेट नंबर छह पर ताला इसलिए लगाया गया था ताकि कांग्रेस विधायक शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री

की कथित विफलता, कथित कृषि घोटाले और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कमियां जैसे मुद्दों को न उठा सकें। उन्होंने कहा, 'सवालों से डरती, जवाबदेही से भागती... ये भाजपा की कैसी भगोड़ी सरकार है जो लोकतंत्र पर ताला लगाती है? विधायकों को सदन में प्रवेश से रोकना और लोकतंत्र के मंदिर पर ताला लगाना, भाजपा सरकार द्वारा सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या करना है।'

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा सुचारु रूप से चले, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि विधायकों को उस दरवाजे से प्रवेश करने से क्यों रोका गया जिसका वे पारंपरिक रूप से इस्तेमाल करते रहे हैं। जूली ने पूछा, जब से विधानसभा बनी है, हम इसी दरवाजे से आते रहे हैं। आज इसे क्यों बंद किया गया? उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक पहले सुबह स्कूल गए जहां उन्हें एक नोटिस दिखाया गया जिसमें कहा गया था कि वे परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, फिर हम पैदल विधानसभा पहुंचे और हमें यहां प्रवेश करने से रोक दिया गया। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक 'आवाज दबाने वाला कानून' लेकर आई है और मांग की कि इस आदेश को वापस लिया जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 3,768 स्कूलों को जर्जर घोषित किया गया था, लेकिन उनमें से किसी में भी पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने आगे दावा किया कि लगभग 85,000 कक्ष खराब हालत में हैं और अध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। कांग्रेस विधायकों के धरने में मौजूद पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, कांग्रेस विधायक शामिल नहीं हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुआ जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया और राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। जूली ने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के आंदोलन को दबाना चाहती है। बाद में ये विधायक जूली की अगुवाई में पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जब विधायकों ने समूह में विधानसभा में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ये विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधायकों को छह नंबर दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तथा दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है।



मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान की समीक्षा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जीआईएस आधारित डेटा अपलोड करने, डेटा लेयरों की मैपिंग एवं परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को अधिक उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सभी आवश्यक लेयरों की मैपिंग प्राथमिकता से पूरी की जाए। श्रीनिवास ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व भूमि की मैपिंग करते समय केवल भूमि का स्थान ही नहीं, बल्कि भूमि की किस्म सहित अन्य

महत्वपूर्ण संबंधित विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। इससे विभागों को अपनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चयन में सुविधा होगी तथा योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्राथमिकता से मैप किया जाए, ताकि परियोजनाओं की योजना बनाने समय विभिन्न विभागों के पास संबंधित क्षेत्र की समग्र एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने प्रदेश में संभावित इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पहचान, उनका विश्लेषण एवं मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने से परियोजनाओं की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों और कनेक्टिविटी से संबंधित कमियां की बेहतर पहचान की जा

सकेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य के पीएम गति शक्ति पोर्टल पर केंद्र सरकार की 29 अनिवार्य लेयर्स तथा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 23 अतिरिक्त लेयर्स की मैपिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य लेयर्स भी मैप की गई हैं। इससे विभिन्न विभागों को परियोजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए एकीकृत भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध हो रही है। बैठक में पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान की प्रगति की भी जानकारी दी गई। इसके तहत बारां जिले द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जबकि धौलपुर, सिराही, करौली एवं जैसलमेर जिलों में मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। जिला स्तर के मास्टर प्लान में स्कूल, अस्पतालबाड़ी, अस्पताल, विद्युत एवं सड़क सहित विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी सुविधाओं से संबंधित डेटा को शामिल किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम

गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जीआईएस आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के डेटा को एक मंच पर उपलब्ध करार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समग्र एवं समन्वित योजना में सहायता करना है। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से परियोजनाओं की प्लानिंग, निगरानी, कनेक्टिविटी का आकलन तथा संभावित गैप्स की पहचान में सहायता मिलती है। बैठक में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, नागरिक विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और गति शक्ति पोर्टल से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

जयपुर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, कंबल में बांधकर खाली जगह पर फेंका शव

जयपुर। जयपुर में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की कथित तौर पर हत्या कर शव को अन्यत्र फेंक दिने जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान टोडारामसिंह निवासी जगदीश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जगदीश का निर्वस्त्र शव सांगानेर सदर थानाक्षेत्र में एक खाली जगह पर कंबल में लिपटा मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया आशंका है कि हत्या के बाद शव को वहां लाकर फेंका गया। सहायक पुलिस आयुक्त भवानी सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस उपनिरीक्षक रिश्तव लेते गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहस्पतिवार को कोटपुतली में एक उपनिरीक्षक को 3,500 रुपये की कथित रिश्तव लेते रहे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार, पुलिस थाना कोटपुतली के उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को रिश्तव मामले में गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के एक बयान के अनुसार, परिव्रादी ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा बैंक के विरुद्ध अदालत के माध्यम से कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परिव्रादी के अनुसार, आरोपी राजेंद्र सिंह इसके अनुसंधान अधिकारी हैं और वे आगे की कार्यवाही करने की एवज में पांच हजार रुपए मांग रहे हैं। शिकायत के संस्थापन के दौरान आरोपी ने रिश्तव मांगते हुए 1500 रुपए ले लिए।



टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार में लाएं तेजी : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को और गति दी जाए। इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार को सघन करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिला स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव गुरुवार को शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्स-रे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लियर एसिड एंटीबिफोर्मेन टेस्ट (छ-ड) बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्ययोजना के साथ परिणामों में सुधार लाया जाए।

श्रीनिवास ने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (ब्रह्म) और डिफेंसिबल टीबी केयर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी रोगी का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के साथ उसके परिवार के पात्र सदस्यों की स्क्रीनिंग और आवश्यकतानुसार प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने माय भारत स्वयंसेवकों को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने, एनसीसी कैडेट्स की ब्लॉक स्तर तक भागीदारी बढ़ाने तथा एनएम्, आशा सहयोगिनी और सीएचओ सहित जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अभियान की प्रगति की

जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई थीं। यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 586, वर्ष 2024 में 3,350 तथा वर्ष 2025 में 6,547 तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख 43 हजार 583 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है तथा टीबी रोगियों को 2 लाख 4 हजार 888 पोषण किट वितरित की गई हैं। वर्ष 2026 में एक्स-रे उपयोग लक्ष्य के मुकाबले 83 प्रतिशत तक पहुंचा है। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में टीबी जांच के लिए 643 छ-ड लैब, 132 हेंड-हेल्ड एक्स-रे यूनिट और 652 फिक्स्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं। अभियान के दौरान 3 लाख 29 हजार से अधिक छ-ड टेस्ट और 35 लाख 87 हजार से अधिक एक्स-रे किए गए हैं। बैठक में एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जोगा राम सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं : जूली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ विधानसभा तक विरोध मार्च निकाल लिया, जिसमें उन्होंने मीडिया पर शिक्षा विभाग की कवरेज करने पर रोक लगा दी। भजनलाल सरकार के आदेश के खिलाफ अब राज्य में मीडिया लोगों को यह नहीं बता पाएगी कि मौजूदा समय में स्कूल कितने जर्जर हो चुके हैं या शिक्षा प्रणाली कितनी बदहाल हो चुकी है। इसी फैसले के विरोध में टीकाराम जूली ने कांग्रेस के अन्य विधायकों के खिलाफ साथ मिलकर विधानसभा तक मार्च निकाला, जिसमें वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों

नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत भी की।

टीकाराम जूली ने कहा कि ये लोग हमें कब तक रोकेंगे। ये लोग हमें नहीं रोक पाएंगे। मैं खुद विधानसभा में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये लोग हमें नहीं रोक पाएंगे। ये लोग बच्चों को रोकना चाहते हैं। ये लोग बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। हर घर में बच्चा है। आखिरकार आप कितने बच्चों को मोबाइल ले जाने से रोकेंगे। आप लोग कितने मीडिया वाले रोकने का काम करेंगे। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उन्होंने नवोदय विद्यालय खुलावाए थे। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एजुकेशन में एक भी काम किया हो, तो आप मुझे बताइए।

उन्होंने कहा कि हम आईटीई



लेकर आए थे। ये लोग अब उसका भगतान तक नहीं कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान हम लोगों ने शुरू करने का काम किया था। लेकिन, अफसोस की बात है कि इन लोगों ने उसे भी बंद करने का काम किया। यही नहीं, सीएसआर का पैसा आरएसएस को दिया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि यह पैसा स्कूलों को दीजिए। अगर यह पैसा स्कूलों को दिया गया होता, तो आज की तारीख में स्कूलों की तस्वीर बदल गई होती।

टीकाराम जूली ने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम पहले ही साल में सारे पद भर देंगे। अफसोस की बात है कि अभी तक सवा लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 3768 स्कूल जर्जर हो चुके हैं। वहां स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। इन स्कूलों को 85 हजार क्लासरूम क्षतिग्रस्त हैं। स्कूल में कोई भी पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन, अफसोस की बात है कि इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। यह सभी भाजपा के पाप हैं और अब इन पापों को भरने के लिए बीजेपी की ओर से एक ढक्कन कानून लाया गया है। ऐसे ढक्कन कानून में अपनी जेब में लेकर चलाता हूँ। ये ढक्कन कानून अब चलने वाला

नहीं है। इस ढक्कन कानून को राजस्थान के बच्चे और जनता उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह फूटगा, बल्कि ढंका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी पूरी फिल्म बाकी है। हम राजस्थान के सभी स्कूलों में जाकर यहां के स्कूलों की जर्जर हालत के बारे में लोगों को बताएंगे। हम इन लोगों को बताएंगे कि मौजूदा समय में स्कूलों की हालत कैसी बनी हुई है। यह छुपाएंगे, लेकिन हम दिखाएंगे। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन अब हम मुद्दों पर बात करेंगे और मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उनके मुताबिक, यह सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।

विद्यार्थियों से जुड़ी शिकायतों की संवेदनशीलता से त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक महेन्द्र कुमार खींची ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग से संबंधित परिवारों की स्थिति, पोर्टल पर उनकी श्रेणीवार प्रविष्टि, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान निदेशक खींची ने शिक्षा विभाग से संबंधित सभी श्रेणियों में प्राप्त परिवारों का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने शिकायतों की प्रकृति, संबंधित विभागीय स्तर तथा निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए

अधिकारियों को परिवारों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खींची ने कहा कि प्राप्त शिकायतों को उनकी प्रकृति एवं विषय के अनुरूप सक्षम स्तर पर शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि अनावश्यक विलंब न हो और परिवारियों को समयबद्ध राहत मिल सके। उन्होंने शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी परिवार की वर्तमान श्रेणी उसके वास्तविक विषय से मेल नहीं खाती, तो आवश्यकतानुसार उसका री-कैटेगरीजेशन किया जाए, जिससे शिकायत संबंधित एवं सक्षम स्तर तक पहुंचकर उसका

उचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही परिवारों की सही श्रेणी निर्धारण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से संबंधित परिवारों का निस्तारण संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ किया जाए, ताकि संबंधित विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सहायता एवं समाधान उपलब्ध हो सके। इस दौरान बालिका सैनिक स्कूल से संबंधित प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। निरीक्षण के दौरान खींची ने परिवार निस्तारण से जुड़े कार्मिकों से संवाद कर पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।

सुविचार

विनम्रता महानता की निशानी है। फलदार वृक्ष की तरह झुके, अहंकार से दूर रहें, सबका सम्मान करें, यही सच्ची महानता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अद्भुत देश भारत!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली की शक्ति एवं सामर्थ्य के बारे में की गई टिप्पणी के बाद ऐसे अनेक क्षेत्रों की चर्चा होना स्वाभाविक है, जिनमें भारत कई 'विकसित' देशों से बहुत आगे है। हमारे देश में साजिशान नकारात्मकता का बहुत प्रचार किया गया, इसलिए लोगों को इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं होता है। भारत में कई लोगों को लगता है कि कथित विकसित देशों में हर कोई सुखी है, वहां सोना बरस रहा है और अपने देश की हर चीज खराब है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है। हर देश की अपनी समस्याएं हैं। अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद, भारत खान-पान के मामले में स्वर्ग है। जितने पकवान बनाते बनते हैं, उतने किसी देश में नहीं बनते हैं। यहां आज भी रोटी बहुत सस्ती है। फलों और सब्जियों का तो कहना ही क्या! गांवों-करबों में दस-बीस रुपए की ताजा सब्जी पूरा परिवार खा सकता है। ऐसा अमेरिका में संभव नहीं है। एक भारतीय नागरिक ने जापान में तरबूज का भाव पूछा तो हैरान रह गया। वहां एक मामूली तरबूज की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग एक हजार रुपए थी, जबकि उससे ज्यादा अच्छा तरबूज यहां बीस-तीस रुपए में बड़ी आसानी से मिल सकता है। गांवों में तो और सस्ता मिल सकता है। अमेरिका में एक किलो आलू की कीमत लगभग 200 रुपए है। भारत की सब्जी मंडियों में बीस-तीस रुपए किलो के भाव में अच्छे आलू मिल जाते हैं। अगर घर के किसी कोने में खाली जगह हो और वहां आठ-दस आलू यूं ही लगा दें तो धरती माता उन्हें कई गुना करके वापस देती है। ब्रिटेन में हरी सब्जियां बहुत महंगी बिकती हैं। अमरुहों के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं, भारतीय मंडियां इन चीजों से भरी पड़ी हैं और कीमतें सामान्य हैं।

भारत में फरवरी के आखिर में जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, कई लोग मौसम को कोसने लगते हैं। वे कहते हैं कि 'काश, हम किसी ठंडे मुल्क में पैदा होते तो बात ही कुछ और होती।' उन्हें एक बार रूस के याकुत्स्क का चक्कर लगाकर आना चाहिए। वहां माइंस पचास डिग्री से. तक तापमान चला जाता है। हर कहीं बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। गर्मियों की अवधि छोटी होती है, जिसमें आलू, गाजर, पत्तागोभी, चुकंदर जैसी गिनती की सब्जियां उगा सकते हैं। सर्दियों में सब्जियां दूसरे इलाकों से मंगानी पड़ती हैं, जो बहुत महंगी होती हैं। बाहर निकलने से पहले भारी-भरकम ऊनी कोट, दस्ताने, टोपी, जूते पहनने पड़ते हैं। अगर नहीं पहनेंगे तो शरीर का कोई हिस्सा सुख पड़ सकता है, जिसे बाद में हटाने की नौबत आ सकती है। एक पर्यटक का कान सुन्न पड़ गया था, जिसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ज़िंदगीभर पछताते। भारत पर सूर्यदेव अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। ठंडे देशों के लोग यहां आकर धूप सेकते हैं, ताकि तन-मन को थोड़ा सुकून मिले। अगर हमने इतनी धूप का सदुपयोग करने के लिए कोई तकनीक विकसित की होती तो आज ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होते। हमें एलपीजी सिलेंडरों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता और हर साल अरबों डॉलर बचते सो अलग। भारत के तीज-त्योहार अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीपावली पर दीपक, तेल और बाती से ही लाखों लोगों तक धन का प्रवाह हो जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र कितने देशों के पास है? हमारे हर त्योहार का कोई-न-कोई वैज्ञानिक आधार जरूर होता है। हमें इन पर गर्व करना चाहिए। अगर हमारे नेता और अधिकारी गंभीरता एवं ईमानदारी से काम करें, जनता अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए तो भारत सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बन सकता है।

ट्वीटर टॉक

कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 'वंदे मातरम' के पूरे गाने के बजाय सिर्फ दो लाइन गाने का फ़ैसला न सिर्फ देश विरोधी है, बल्कि पार्लियामेंट के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।

१९३७ में, तुहीकरण के लिए, कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम' को दो हिस्सों में बाँट दिया था।

–अमित शाह

कांग्रेस ने हमेशा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को देश बनाने का एक जरूरी हिस्सा माना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेकर 'प्रोजेक्ट टाइगर' तक और संविधान में आर्टिकल 48- और 51-(स) जोड़कर, नेचर की सुरक्षा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्युटी बनाया।

–अशोक गहलोत

कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा 'वंदे मातरम' के केवल दो छंद गाने का निर्णय एक बार फिर उनकी तुहीकरण की राजनीति को उजागर करता है। 19३7 में भी कांग्रेस ने अपनी मूल भावना से समझौता किया था, और आज भी वही मानसिकता स्पष्ट है।

–भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

जीव का मूक प्रेम

महादेवी वर्मा एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रही। इस दौरान उनकी पालतू गिलहरी गिज़ू, जिसे उन्होंने स्वयं मरणासन्न अवस्था से बचाकर पाला था, घर पर अकेली रह गई। जब भी महादेवी के कमरे का द्वार खोला जाता, गिज़ू अपने झूले से उतरकर तेज़ी से दोड़ती, किंतु द्वार पर किसी और को देखकर उसी तीव्रता से वापस अपने घोंसले में लौट जाती। घर के सभी लोग उसे प्रतिदिन उसका प्रिय भोजन काजू देने का प्रयास करते रहे। अस्पताल से लौटने पर जब महादेवी ने गिज़ू के झूले की सफाई की, तो उन्हें वहां काजू के दाने जमा मिले, लगभग अछूते। इससे यह प्रकट हुआ कि गिज़ू ने उन दिनों अपना प्रिय भोजन लगभग त्याग ही दिया था, मानो प्रतीक्षा और विरह में उसकी भूख ही पर गई हो।

महादेवी लौटती तो गिज़ू अस्वरथ लेखिका के तकिए के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाने लगी, ठीक किसी समर्पित परिचारिका की भांति।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor: Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor- Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No.: TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञानों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादकों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाना के प्रकार किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

प्रमोद भार्गव

मोबाइल : 9981061100

भा

रत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पहले जम्मू-कश्मीर दौरे में यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न और अहम भू-भाग बताया। ताकि सुरक्षा के लिहाज से सराहना की। अमेरिकी राजदूत का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर चौंका देने वाला होने के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों में बदलाव का उल्लेखनीय संकेत है। लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखी जाती रही है। जिसे अक्सर भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का यह दो टूक बयान कश्मीर की धरती पर देना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकंटे में है।

यह रहे अमेरिका ने वर्ष 2018 से ही जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर अपने नागरिकों को यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी हुई है। इस नसीहत को चौथी श्रेणी में रखा हुआ है। गोर ने फिलहाल इस यात्रा चेतावनी को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बिंदु पर अमेरिका यात्रा में छूट दे सकता है ? हालांकि उस समय धारा-370 बहाल थी और घाटी में आतंकी संकट की छाया छाई रहती थी। अगर 2019 में धारा-370 और 35-ए को भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते विलोपित कर दिया, उसी के बाद से कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों में निरंतर सुधार हो रहे हैं और पत्थरबाजी व अन्य आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उक्त चेतावनी की फिर से पुष्टि करते हुए नई एडवायजरी जारी कर दी थी। जो अभी भी लागू है। चूंकि गोर दक्षिण एशिया व मध्य एशियाई मामलों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी कश्मीर यात्रा और दो टूक बयान की अपनी अलग अहमियत है। खासतौर

पर तब जब पाकिस्तान के संबंध भी अमेरिका के साथ फिलहाल मधुर बने हुए हैं और अमेरिका ईरान से लड़े जा रहे युद्ध में पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान से उमर अब्दुल्ला को भी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि वे कुछ दिनों से धारा-370 की पुर्नबहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जून-2026 में द हिंदू हडल (अंग्रेजी समाचार पत्र) सत्र के दौरान कहा था कि 2019 में 370 को हटाना भारत सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत भूल थी। साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक अधिकारों की बहाली की भी मांग की थी।

पाकिस्तान धर्म की घुड़ौ पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है। जबकि उसे सबसे मुकम्मल उत्तर ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर करारा जवाब देना होगा। दरअसल इस समय पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। यहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को भूतने का काम हाल ही में किया है। पाक की ये हरकतें इसलिए भी बरकरार हैं, क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को विवश करना पड़ रहा है। अब जाकर उसे कश्मीर मुद्दे पर

अमेरिका का दो टूक जवाब मिला है।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कड़ता पर चोट नहीं कर पाना है। गोया, साफ है कि यह समस्या अब राजनैतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है, बल्कि धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिंसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदों और मंदिरों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं।

मुस्लिमों की इस दोषपूर्ण मंशा को संविधान निर्माण के समय ही डॉ भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो अंबेडकर ने स्पष्ट लहजे में कहा था कि आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले, लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते? मैं देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय या विश्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं। विडंबना देखिए कि मुस्लिम समाज देश में हर जगह बृहद हिंदू समाज के बीच अपने को

नजरिया

गठबंधन या मजबूरी का बंधन?

उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक शाश्वत नियम रहा है-यहाँ दिल्ली का रास्ता तो तय होता है, लेकिन प्रांतीय स्वाभिमान और क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षाओं के टकराव में बड़े-से-बड़े राष्ट्रीय एजेंडे भी ध्वस्त हो जाते हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने देश के सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक चमत्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ‘अजेय थर’ की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, तो देश भर के विपक्षी रणनीतिकारों को लगा कि उन्होंने भाजपा की चुनौती मशीनरी की अचूक काट ढूँढ ली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, जिसे ‘यूपी के दो लड़के’ कहकर प्रचारित किया गया, ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म दिया। इस समीकरण को जनता का भारी समर्थन मिला और गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटों पर ऐतिहासिक विजय पताका फहराई। परंतु, राजनीति में जीत जितनी सुखद होती है, उसकी विरासत को संभालना और आगामी संघर्षों के लिए उसे अक्षुण्ण रखना उतना ही दुरुह कार्य होता है। आज, 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही, इस सफल गठबंधन की नींव हिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों तक यह चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ‘सब कुछ ठीक नहीं है’। यह दरार अब केवल बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया के अखाड़े तक खुलकर सामने आ रही है।

इस गहरे अविश्वास, जमीनी अंतर्विरोध और दोनों दलों के बीच जारी वर्चस्व की जंग का सबसे ताजा, ज्वलंत और चिंताजनक उदाहरण हाल ही में सहारनपुर में आयोजित ‘दिशा’ की आधिकारिक बैठक के दौरान देखने को मिला। जिला स्तर पर विकास कार्यों, प्रशासनिक तालमेल और स्थानीय जनसमस्याओं (विशेषकर एक नाले के निर्माण और विकास कार्यों की अनदेखी) की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में जो कुछ हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा यश प्रश्न खड़ा कर दिया है। बैठक के दौरान कांग्रेस के कदावर सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक आशु मलिक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस विकास कार्यों के दायरे को लांचकर व्यक्तिगत आक्षेपों, सांगठनिक श्रेष्ठता की जंग और तू-तू-मैं-मैं के अमर्यादित स्तर पर पहुंच गई। दोनों नेताओं के बीच करीब सात से आठ मिनट तक चली इस तीखी जुबानी जंग का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। यद्यपि, राजनीति के तयशुदा व्याकरण के अनुसार, घटना के अगले ही दिन दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भारी डेमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दीं। यह बयान जारी किए गए कि यह महज जनप्रतिनिधियों के बीच स्थानीय विकास कार्यों को लेकर हुई एक सामान्य प्रशासनिक बहस थी और इसे राजनीतिक गठबंधन के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत में इस तरह के सार्वजनिक और तीखे टकराव कभी भी महज प्रशासनिक मतभेद नहीं होते। यह वाक्या उस ज्वालामुखी का एक छोटा सा विस्फोट है जो पिछले कई महीनों से दोनों पार्टियों के प्रांतीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलों में सुलग रहा था। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्तर पर जीत के बाद भी दोनों पार्टियों के बीच गहरी दरार है।

इस रार और अविश्वास की जड़ें केवल स्थानीय मुद्दों या किसी नाले के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। इसकी असली वजह 2027 की चुनौती विसात पर अपनी-अपनी ताकत दिखाने और भविष्य की सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करने की एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। 2024 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। पार्टी के रणनीतिकार, नए सांगठनिक प्रभारी और प्रांतीय नेता अब राज्य में खुद को समाजवादी पार्टी के ‘जूनियर पार्टनर’ या ‘पिछलगु’ के रूप में देखने को कतई तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के भीतर से लगातार यह मांग उठ रही है और सार्वजनिक मंचों से यह बयान दिए जा रहे हैं कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेगी। पर कम से कम भीतर एक बड़ा धड़ा साफ तौर पर काम से कम 150 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर हुई वापसी, राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और उनके द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव के बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अकेले दम पर 37 सीटें मिलना किसी भी स्तर में संभव नहीं था। कांग्रेस का मानना ​​है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के चेहरे और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख को देखकर इस गठबंधन की ओर आकर्षित हुआ था। इसलिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि

उनके बिना राज्य में भाजपा-विरोधी कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में भाजपा-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ‘बड़ा भाई’ और एकमात्र वास्तविक विकल्प मानती है। अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों का स्पष्ट मानना ​​है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर वास्तविक संगठन, समर्पित कैडर, बूथ मैनेजमेंट और सांगठनिक मशीनरी केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पास है।

वोटो के इस आंतरिक ध्रुवीकरण और वर्चस्व की मूक जंग में सबसे बड़ा पेंच मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर फंसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने बिना किसी दुविधा के, बेहद समझदारी से भाजपा को हराने के लिए एकमुश्त इस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। परंतु अब, कांग्रेस को यह साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय और गैर-जाटव दलित मतदाता दोबारा अपने पुराने और पारंपरिक घर यानी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसी मुस्लिम-दलित-सवर्ण गठजोड़ के पुराने फॉर्मूले को पुनर्जीवित कर अपने वाला प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मान रहे हैं।

इसके उलट, समाजवादी पार्टी अपने इस मुख्य आधार-जिसके दम पर वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है-को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती। सपा को डर है कि यदि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसका क्षेत्रीय क्षत्रप और राज्य की राजनीति का मुख्य ध्रुव होने का दर्जा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। सहारनपुर की घटना और उसके बाद इमरान मसूद जैसे नेताओं के तीखे बयान इसी वोट बैंक पर अपने-अपने प्रभाव को साबित करने की एक अघोषित और आक्रामक जंग का हिस्सा हैं।

यह बात को प्रमुखता से रेखांकित होती है कि शीर्ष स्तर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आपसी केमिस्ट्री चाहे जितनी भी मजबूत, सोहार्दपूर्ण और परिपक्व दिखाई दे, जमीन पर व्यावहारिक राजनीति केवल व्यक्तिगत दोस्ती या मुरकुराती हुई तस्वीरों से संचालित नहीं होती। व्यावहारिक राजनीति हमेशा कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं, स्थानीय नेताओं के अस्तिव्य के संकेत और क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों से संचालित होती है। शीर्ष स्तर के नेता भले ही दिल्ली या लखनऊ में बैठकर बंद कमरों में कोई समझौता कर लें, लेकिन जब तक बूथ स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिलेगा और वोटों का ट्रांसफर पूरी ईमानदारी से साफ-पूरे रूप से पक्ष में नहीं होगा, तब तक किसी भी गठबंधन की सफलता केवल एक किताबी कल्पना ही रहेगी।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor: Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor- Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No.: TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञानों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादकों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाना के प्रकार किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कुछ आधिकारिक भेदवाताओं के अलावा, न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांसेस (आईओसी) की अमेरिकी इकाई द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीयों के साथ एक मुलाकात का कार्यक्रम भी रेड्डी के अमेरिकी दौरे के जूझें में शामिल है। इससे पहले, बृहस्पतिवार तड़के नई दिल्ली हवाई अड्डे पर कांसेस सांघव मल्लू रवि और राजय सरकार के प्रोटोकॉल मानकों के सलाहकार हस्करा वेणुगोपाल ने उन्हें विदा किया। रेड्डी बुधवार को कांसेस कार्य सभिती की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे।

विज्ञान के अनुसार, "यह रईस फिल्मों इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेखन कम चर्चित अथवा उपेक्षित केंद्रित है, जो कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी के जीवन के 21 दिन को दिखाता है। ऐसे समय में जब देश आजादी की दहलीज पर कदम रख रहा था और दिल्ली सत्ता का केंद्र बन रही थी, गांधी ने वहां से दूर जाने का एक अप्रत्याशित फैसला किया।" निम्नानुसार, "नए एक बयान में कहा, लेकिन वहां से दूर जाकर उन्होंने भीख छेदन का काम किया किया, बल्कि खुद को नए सिरे से परिभाषित किया। इतिहास की किराया भले ही उस देश की कीमतों के प्रति भाव है। सामान्य घटनाओं को दर्ज करती हैं।"



उन्की जलनी शिंङ्गिनी रावल,
अभिषेक जोलन और सुछी जङ्गल
कपूर को उन्की यात्रा को सम्फल
बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
अभिनेत्री नरे लख्ठा, और ये सब मेरे
भांजे के बर्थडे वारे दिन हुआ, तो
आँर भी जादू जैसा लगा। मैं दिल से
आभारी हूँ। आप सबकी और ऊम्बर
आपनी हैं। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते
हैं जिन्हें हर्षा दिल में संभाल कर
रखना चाहिए। हर हर महादेव।
अभिनेत्री अहाना कुमरा एक
प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके
पिता सुशील कुमरा ल्यूमिनोस
प्रिन्सिटेड (स्वा देश के) जानी-नाम
कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जबकि
मां सुरेश कुमरा वाराणसी की पूर्व
डीएम्पी रह चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति
पदक से भी सम्मानित किया जा
चुका है।

फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ भूमि शेट्टी, रोहित सराफ और कई अन्य प्रमुख कलाकार नजर आनेवाले हैं। भव्य सिनेमाई स्तर पर तैयार की जा रही 'महाकाली' में शक्तिशाली भारतीय इतिहासनिष्ठ कथानक, शानदार विजुअल्स, विस्तृत वर्ल्ड-बिल्डिंग और बड़े पैमाने की कहानी के जरिए दर्शकों को एक इमर्सिव बड़े पैमाने का अनुभव देने का वादा किया गया है।

जादवपुर विश्वविद्यालय में एसएफआई और अन्य वामपंथी छात्र संगठनों के साथ हुई झड़प के बाद, कोलकाता में विश्वविद्यालय गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस।

का जवाब दे सकता है। हालांकि, शोकेर्त्ताओं ने कहा कि एआई भले ही कैंसर के उपचार को समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराता है, लेकिन अपने मौजूदा स्वरूप में यह पक्के तौर पर साबित नहीं करता कि किसी खास बीज के संस्कार में आने से डीएनए को हुआ नुकसान ही कैंसर का कारण बना। शोध दल में गुवाहाटी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एफआईईआर) और बैंगलोर में औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएनआईए) -

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मानसिक स्वास्थ्य, सहनशीलता और भावनात्मक कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली से कच्चाकुमारी तक आयोजित मोटर्ससाइकिल रैली 'ए राइड फॉर रेजिलियंस' और 'बियॉन्ड द हॉराइजन' के लॉन्च में शामिल हुई बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर।

